Page Three
Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment
Property
Business Opportunity
Vehicles
Announcements
Antiques & Collectables
Barter
Books
Computers
Domain Names
Education
Miscellaneous
Entertainment & Event
Hobbies & Interests
Services
Jewellery & Watches
Music
Obituary
Pets & Animals
Retail
Sales & Bargains
Health & Sports
Travel

Matrimonial (Sunday Only)

अब मात्र रु. 20 प्रति शब्द

सीएम ने सदन में दी कोरोना पर सरकार की तैयारी की जानकारी

विस सत्र

कोरोना को भारत एवं उत्तराखंड परास्त करने के लिए प्रतिबद्धः सीएम

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि कोरोना एक अति गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि कोरोना को भारत एवं उत्तराखंड परास्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना वायरस महामारी को रोकने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन एवं चिकित्सा विशेषज्ञों से सलाह लेते हुए हमारी सरकार ने अनेकों प्रभावी कदम उठाए हैं। अधिकारियों की ओर से लगातार स्थिती पर निगाह रखी जा रही है। इस महामारी से लड़ने के प्रयास में उत्तराखंड भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों के अन्तर्गत एपिडेमिक डिजीज कन्ट्रोल एक्ट–1897 के प्राविधानों के अंतर्गत कोविड–19 रेगुलेशन राज्य में लागू किया गया तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही मंत्रिमंडल की दो आपात बैठकें, इसी चुनौती से निपटने के लिए की जा चुकी हैं।

राज्य में संक्रमण की संभावना को देखते हुए भारत नेपाल सीमा की समस्त चौकियों में जनपद चंपावत के बनबसा व टनकपुर में, जनपद पिथौरागढ के धारचुला, बलुवाकोट, जोलजीवी, बालाघाट व ड्यूरा में तथा जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।

विधानसभा सत्र के लिए जाते हुए मुख्यमंत्री एव धनसिंह रावत।

अब तक उक्त जगहों पर 55,109 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें कोई भी कोरोना संक्रमण संदिग्ध नहीं मिला है। प्रत्येक स्क्रीनिंग प्वाइंट पर मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, इन्फारेड थर्मोमीटर की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया गया है। राज्य में एयरपोर्ट अथॉरिटी से समन्वय करते हुए देहरादून, पन्तनगर व पिथौरागढ एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से 50,016 यात्रियों स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जिसमे कोरोना वायरस के संदिग्ध लक्षण वाला कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया।

वर्तमान में घरेलू उड़ाने भी पूर्णतः बन्द कर दी गई है

देहरादून। 31 दिसम्बर 2019 के बाद से चीन व अन्य प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की सूची समय–समय पर भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को प्रदान की जा रही है, वर्तमान तक 2082 लोगों की सूची प्राप्त की गई है और इन सभी की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा चुकी है। उक्त सूची में से 628 लोग 28 दिन की निगरानी अवधि पूर्ण कर चुके हैं। 131 लोग राज्य से बाहर जा चुके है एवं अब तक 1,323 लोग निगरानी अवधि (1244 घर में व 79 चिकित्सालय में) पर हैं।

नॉन एसेंशियल सर्विस में वर्क फ्रॉम होम के आदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि विषाणू के आने का प्रमुख मार्ग राज्य में नये व्यक्तियों का आवगमन ही है इसलिए सभी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को 20 मार्च 2020 से अग्रिम आदेशों तक प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। भीड़ को रोकने के लिए सभी स्कूल, कालेज, सिनेमा हाल, मॉल आदि 31 मार्च 2020 तक बंद किए जा चुके हैं एवं भारत सरकार के निर्देशों के कम में यह अवधि बढ़ा दी गई है। भारत में उत्तराखंड की ओर से 31 मार्च, 2020 तक लॉक डाउन घोषित किया गया था, जो एक अग्रणी पहल थी एवं भारत सरकार के निर्देशों के कम में यह अवधि भी बढ़ा दी गई है। जनपदों के की ओर से इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जा है। नॉन एसेंशियल सर्विस में वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एंव उपचार के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एंव उपचार के लिए राज्य कैबिनेट की ओर से 50 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है तथा मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी 10 करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई गई है। राज्य एवं जनपद स्तर पर रेपिड रेस्पॉन्स टीम (आरआरटी) का गठन किया गया है तथा विकासखंड एवं ग्राम स्तर पर एएनएम व आशा कार्यकत्री ग्राम प्रधान व ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से जन जागरूकता व प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

सीएम ने की उत्तराखंड के नागरिकों से यात्रा न करने की अपील

देहरादून **संवाददाता**। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के नागरिकों से यह अपील है कि वे भी अनावश्यक यात्रा से बचे, जिससे कि वे और उनका परिवार सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले भाई–बहनों से लेकर, सामग्री एवं सेवाओं की आपूर्ती में लगे कर्मियों, पुलिस कर्मी तथा विशेषकर वह चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ जो अपने व्यक्तिगत सुरक्षा को जोखिम में डालते हुए भी इस कार्य में निरंतर लगे व्यक्तियों को विशेष साधूवाद दिया। उन्होंने अनुरोध किया कि वे अपनी सुरक्षा में भी कोई कोताही न बरतें। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किए गए अनेक प्रयासों में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है, जबकि इसमें संपूर्ण जन–सहभागिता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की ओर से लागू किए गए 21 दिनों के इस महायज्ञ में संयम एवं सकल्प की आहुति देते हुए अपने आस पास के सभी नागरिकों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने एवं अफवाहों से बचने का अनुरोध किया।

कालाबाजारी की रोकथाम के लिए छापेमारी की कार्रवाई की जा रही

देहरादून **संवाददाता**। कोरोना कोविड–19 के टेस्ट के लिए हल्द्वानी मेडिकल कालेज के अतिरिक्त एम्स ऋषिकेश तथा इडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम की अनुमति आईसीएमआर से प्राप्त हो गई है। मास्क व सैनेटाइजर को आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। इनकी कालाबाजारी की रोकथाम के लिए छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में बीते रोज चार कोविड–19 रोगियों की पुष्टि हुई है तथा कन्टैक्ट टेसिंग के माध्यम से इनके संपर्कों पर आने वाले सभी व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

ओकाया पावर ग्रुप ने सुपरस्टार रणवीर सिंह को ब्रांड एंबेसडर बनाया

देहरादून **संवाददाता**। राज्य में 2082 व्यक्तियों की पहचान की गई है, जो चीन तथा अन्य कोविड–19 प्रभावित देशों से यात्रा करके आये हैं जिनको 28 दिनों के लिए निगरानी में रखा गया है। इनमें से 628 व्यक्ति 28 दिनों की निगरानी अवधि पूर्ण कर चुके हैं। वर्तमान में 1323 व्यक्ति 28 दिन की निगरानी में हैं। राज्य में अब तक 237 सैंपल लिए गए हैं जिनमें से 162 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इनमें से 158 सैंपल निघ्गेटिव पाए गए हैं और 04 केस पाजिटिव पाये गये हैं। आतिथि तक 75 सैंपल की रिपोर्ट प्रतीक्षारत है, जिनकी जनपद स्तर की ओर से स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लागू किये गये 21 दिनों के इस महायज्ञ में अफवाहों से बचने का अनुरोध किया।

आवश्यक सेवाओं एवं सामग्री की आपूर्ती की जा रही सुनिश्चित

संवाददाता

देहरादून। लाक डाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं एवं सामग्री की आपूर्ती सुनिश्चित की जा रही है तथा निम्न आयवर्ग को दिक्कत न हो इसीलिए सरकार की ओर से ईएसआई में पंजीकत श्रमिकों को 1000 प्रतिमाह वितरित किया जा रहा है। राज्य के ऐसे श्रमिक हैं, जो पंजीकृत नहीं है उनको मूलभूत खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 30 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी है। यह सब प्रयास इसलिए की जा रहें है ताकि इस लॉकडाउन अवधि में कोई भी गरीब परिवार खाद्यान से वंचित न रहें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों में पुलिस विभाग एवं एसडीआरएफ का सहयोग लिया जा रहा है तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। सभी संभावित कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों का उपचार निश्शुल्क किया जा रहा है। प्रभावी समन्नवय, त्वरित कार्रवाई, जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए राज्य स्तर पर कन्ट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है। सभी संचार माध्यमों की ओर से कोविड–19 के संक्रमण से बचने के लिए सलाह जारी की जा चुकी है तथा निरंतर सलाह प्रसारित की जा रही है। इसी प्रायोजन के लिए समर्पित टोल फ्री हैल्पलाइन नंबर 104 अथवा दूरभाष नंबर 0135–2609500 है।

■ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 30 करोड़ निर्गत

इसके अतिरिक्त राज्य स्तर द्वारा हैल्पलाइन के माध्यम से भी इन लोगों से भी दूरभाष द्वारा संपर्क साध कर दैनिक स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है। इसके साथ–साथ समस्त जनपदों में आइसोलेशन फैसिलिटी व संस्थागत क्वारेंटाइन की व्यवस्था की गई है। समस्त प्रमुख चिकित्सालयों व मेडिकल कालेज संस्थानो में पृथक से आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है और वर्तमान में 933 आइसोलेशन बेड विभिन्न चिकित्सालयों मे कोरोना वायरस के लिए आरक्षित है। इसके साथ–साथ समस्त जनपदों में संस्थागत क्वारेंटाइन के लिए 1384 बेड की व्यवस्था की गई है।

दून मेडिकल कालेज में कोविड–19 की सेवाओं के लिए समर्पित

संवाददाता देहरादून। दून मेडिकल कालेज में कोविड–19 की सेवाओं के लिए समर्पित किया गया है। राजकीय दून मेडिकल कालेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज तथा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मुख्य रूप से कोरोना उपचार के लिए आरक्षित रखा जाने का प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव संसाधन की कमी के दृष्टिगत उत्तराखंड मेडिकल चयन बोर्ड की ओर से पूर्व विज्ञापन के 314 पदो पर नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त 562 नये पदो पर भर्ती करने के आदेश किए गए हैं। श्रीनगर, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष को आगामी 03 माह के लिए इन्टरव्यू द्वारा संविदा पर पदों के सापेक्ष डॉक्टरों की भर्ती करने के अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी भी चिकित्सालयों के लिए अपने स्तर से भर्ती कर सकेंगे। इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट की ओर से अनुमोदित कर लिया गया है। नर्सों की कमी को देखते हुए विभागाध्यक्षों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नर्सों की नियुक्ति के अधिकार दिए गये हैं।